कई गांवों में सामूहिक रूप से बलात्कार किए गए है। लेकिन वहां को सरकार का ध्यान इस माहिलों की सुरक्षा की तरफ नहीं है। यहां तक पुलिस विभाग के अधिक्षक से लेकर डी0आई0जी0 से लेकर अन्य अधिकारियों के द्वारा शैडयूल्ड कास्ट की महिलाओं पर बलात्कार के कई मामले सामने आए है। राजस्थान में दौसा ज़िले की एक शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब महिला के साथ डी0आई0जी0 मधुकर टंडन ने बलात्कार किया लेकिन अभी तक उस डी0आई0 जी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि आज राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसका ध्यान शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ नहीं है। उनके प्रति भलमनसाही की और उनकी रक्षा करने की भावना नहीं है। उस महिला ने कोर्ट में धरा 164 के अंदर बयान दिया है कि उस डी0आई0जी0 ने उसके साथ बलात्कार किया है लेकिन वहां की सरकार ने अभी तक कोई भी कदम उस डी0आई0 जी0 को गिरफ्तार करने के लिए नहीं उठाया। मैं इसलिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा । यू0पी0 के अन्दर मेरठ की बात लें जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे है, यह घटनाएं कुछ दिनों से जब से यह सरकार सत्ता में आई है शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं ज्यादा बढ़ी है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं के साथ जो बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, इनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।

RE: NON-AVAILABILITY OF CIVIC AMENITIES TO 80,000 SLUMS ON ACCOUNT OF AIRPORTS AUTHORITY'S WRONG STAND

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदया, आपने मुझे दस विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं। मेरा विषय है मुम्बई में ए अरपोर्ट अथारिटी के ज़मीन पर बसे 80 हजार झोपडों में रहने वाले तकरीबन सवा दो लाख झौपड़पट्टी-वासियों की समस्या। यह झोपड़पट्टी वासी पिछले 50-60 सालों से वहां रह रहे हैं। मैडम, आप भी मुम्बई की है आप जानती होंगी कि सांताक्रुज और अंधेरी के बीच में दोनों ए अरपोर्ट के आसपास तकरीबन 80 हजार झोपड़े है और उन झोपड़ों में आज तक मुम्बई महानगर पालिका ने कोई भी नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है, न पानी है, न बिजली है और न वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था है और न ही अन्य कोई व्यवस्था है। जो झोपड़े हैं वह भी अच्छी तरह से नहीं बन पा रहे है। इसकी वजह सिर्फ इतनी ही है कि ए अर-पोर्ट अथारिटी उन्हें परमिशन नहीं दे रही है। उपसभापति महोदया, मुम्बई महानगर पालिका पर ए अर पोर्ट अथारिटी ने यह ऐसा कंट्रोल रखा है, उसको एन0ओ0सी0 नहीं दे रही है ताकि मुम्बई महानगर पालिका उनको नागरिक सुविधाएं दे सके।मेरे विषय से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि अगर ए अर पोर्ट अथारिटी की ज़मीन के ऊपर झोपड़े बने हुए है और उन झोंपडियों में सिविक अमेनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं तो उसी ज़मीन पर एक पांच सितारा होटल लीला पेंटा कैसे बन कर तैयार हो गया? पांच सितारा होटल लीला पेंटा में सारी सुविधाएं हैं, पानी भी है, बिजली भी है और अन्य नागरिक सुविधाएं भी है। मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा होटल बनाने की परमिशन कैसे दी गई उसी जमीन पर, ए अरपोर्ट अथारिटी की ज़मीन पर । यह जो परमिशन दी गई है, इस समय हमारे बीच में नहीं है, हमारी राज्य सभा के सदस्य है, उस समय वह नागरिक उड्डयन मंत्री थे माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी। ऐसा बताया जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद जी के ज़माने में उन्होंने यह परमिशन दी थी कि इस होटल को यहां पर बनाया जाएं। (व्यवधान)

उपसभापति : अब चूंकि वह मंत्री नहीं है (व्यवधान)

श्री संजय निरूपमः नहीं उससे पहले आपको जानकारी नहीं है 10-12 साल (व्यवधान)

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): He is a Member of this House..... *(Interruptions)....*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am explaining to him..... *(Interruptions)*

श्री संजय निरूपमः मेरा सवाल यह है कि जब यहां ए अरपोर्ट अथारिटी की ज़मीन पर पांच सितारा होटल बनाया जा सकता है तो उस ज़मीन पर हमारे जो झौंपडियों में लोग रहे है उनको वैद्यता क्यों नहीं दी जा रही है? उनको नागरिक सुविधाएं देने में ए अरपोर्ट अथारिटी क्यों अड़चन लगा रही है? क्या इसकी वजह सिर्फ यह है कि ए अरपोर्ट के आसपास के इलाके में झोपडियां बना देंगे तो हवाई जहाज़ के लेंडिंग और टेक-आफ में कोई प्रोब्लम न आएं? महोदया, झोंपडियां तो बहुत छोटी होती है, उनकी हाइट बहुत कम होती है। अगर उनकी हाइट से हवाई जहाज़ के लेंडिंग और के लेंडिंग और टेक-आफ में कोई प्रोब्लम हो रही है तो क्या पांच सितारा होटल जो बहुत ऊंचा है, जिसकी अच्छी खासी ऊंचाई है, उसकी वजह से हवाई जहाज़ की लेंडिंग और टेक-आफ में क्यों प्रोब्लम नहीं आ रही है? मैं आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं कि लीला प्रेटा होटल को जो परमिशन दी गई है और जो उसके साथ वहां

पर झोंपडियों हैं उनके साथ नाइन्साफी हो रही है, हमारो सरकार इसकी छानबीन कराए और जल्दी से जल्दी ए अरपोर्ट अथारिटी को यह आदेश दिया जाए, सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री की तरफ से यह आदेश उनको जाए कि जल्दी मुम्बई महानगर पालिका के समझ अपना एन0ओ0सी0 रखे ताकि 80 हजार झोंपडियों में जो तकरीबन सवा दो लाख लोग रह रहे हैं उनको सुख-सुविधाएं मिल सके वरन् वह पिछले 50-60 सालों से नरक की ज़िन्दगी जी रहे हैं, पता नहीं आगे कब तक वह इस तरह की जिन्दगी जीने के लिए अभिशप्त रहेंगे। धन्यवाद।

RE: DEATH OF HUNDREDS OF INDIANS IN GREECE BOAT TRAGEDY

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I rise to refer with profound grief and sorrow to the drowning of 227 Indian nationals off the Malta Coast in the Mediterranean Sea. This notorious event is internationally called as "Christmas-day massacre." It is surprising how our authorities allowed 250 people to leave the country by air form Bombay and Delhi and to go through Cyprus, Turkey and Syria and finally to board the vessel. The vessel which is known as 'Yohan' was a hired one. The Capitan and the owner of the vessel are wanted by the Interpol. There are only 22 persons who survived in this tragedy and they have been brought back. So far, in this connection, the C.B.I, has booked only two travel agents. What is the Govemment doing about the Emigration Authorities? What is the Govemment doing about the Police who allowed the people to slip out of this country? And, what is the Government doing about the Passport officials who issued them the passports? I can understand that the authorities within our country did not know the *bonafides* of the ship but what were our diplomatic missions doing in those foreign countries—Cyprus, Turkey and Syria—about the antecedents of the vessel? I think it is a gross violation of the rules, a conspiracy by the officials involved in these Govemment agencies. The C.B.I, has booked only two travel agents. Therefore, I would request the Govemment to see to it that the families are properly compensated because they are the poor people, and the poor farmers, who paid four to eight thousand dollars and the entire transaction was done *benami.* There is no reply from anyone because it is by fly-by-night operators. I hope the Govemment will come to the rescue of these poor families. In this tragedy 227 people have died. They lost their money and lives and the Govemment is doing nothing about it. Therefore, I want the C.B.I, to seek an explanation from the Emigration officials, the Police officials, the Passport officials and also from the Indian missions in these three countries, as to how they allowed so many people to gather at the port. I would like the Govemment to make a statement in this regard. The Home Ministry and the External Affairs Ministry will do justice by making a statement before this House clarifying the position. Thank you.

SPECIAL MENTION

DELAY IN GIVING CONCURRENCE TO DIVERSION OF FOREST LAND FOR LOKTAK DOWNSTREAM HYDRO-ELECTRIC PROJECT IN MANIPUR

SHRI W. ANGOU SINGH (Manipur): This is a Special Mention lying pending from the last Session. This is relating to the delay in giving concurrence to the diversion of forest land for Loktak downstream Hydro-Electirc Project in Manipur. Madam, it is for the utilisation and diversion of 250 hectares of forest land in the State of Manipur for the said Loktak downstream Hydro-Electriic Project. The State Government has already approached to the Govemment of India for giving its concurrence for utilisation of this land. Though the environmental aspect has been cleared by the Govemment of India, cleamance for the forest land is still pending. The environmental aspect has been cleared on 14th April, 1995. Clearance for utilisation of forest land is still lying with the Govemment. Since the project is mainly for power generation to supplement the power in the State, it is highly necessary to start it immediately.

Earlier, there was the problem in regard to funds. But now it has been included under the